अपने सहयोगियों के साथ धरातल मिली सफताओं की दास्तानें

हरियाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना

क्योटो प्रोटोकॉल की स्वच्छ विकास व्यवस्था के तहत कार्बन ट्रेडिंग परियोजना के लिए हरियाणा के सिरसा जिले में आठ गांवों के 227 किसानों की 370 एकड़ रेतीली जमीन का चयन वानिकीकरण के लिए किया गया है। यह परियोजना नौ साल से चल रही हरियाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना का हिस्सा है जिसे यूरोपीय संघ से 2.35 करोड़ यूरो का अनुदान मिला। परियोजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा के ग्यारह जिलों में ग्रामीण समुदाय की हिस्सेदारी से प्राकृतिक संसाधनों के स्थायी प्रबंधन की व्यवस्था विकसित करना है।

यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक (ईआईबी) से एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया (एग्जिम बैंक) को कर्ज

नवीकरण योग्य ऊर्जा और ऊर्जा कुशलता की परियोजनाओं से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ईआईबी 15 करोड़ यूरो का निवेश समर्थन दे रहा है।

हाई नूनः हिमालयी हिमनदों के सिकुड़ने और बदलते मानसून के कारण उत्तरी भारत में जल संसाधनों की बदलती स्थिति के अनुरूप ढलना।

इस शोध परियोजना का मुख्य मकसद हिमालयी हिमनदों के घटने और भारतीय ग्रीष्म मानसून में सम्भावित बदलाव के मद्देनजर उत्तरी भारत में जल संसाधनों के वितरण में परिवर्तन के मद्देनजर स्थिति का ढालने की रणनीति अपनाने की सिफारिशें करना है।

यूरोपीय संघ

भारत के लिए प्रतिनिधिमंडल
65 गोल्फ लिंक्स, 110003 नयी दिल्ली
फोनः +91–11–24629237, 24629238
फैक्सः +91–11–24629206
वेबसाइटः www.delind.ec.europa.eu

जलवायु परिवर्तनः ईयू और भारत

जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए ईयू ने उठाए अनिवार्य कदम

ताजा अनुमानों के अनुसार ईयू–15[1] क्योटो संधि के तहत 8 प्रतिशत उत्सर्जन कटौती के लक्ष्य 2012 तक हासिल कर लेगी। इसके लिए कई नीतियां और उपाय किए जा रहे हैं जिनमें अन्य देशों की परियोजनाओं से उत्सर्जन कटौती की खरीदारी करना और वातावरण से कार्बन सोखने के लिए वानिकी गतिविधियां चलाना शामिल है।

ईयू–15 का ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन 2008 में 6.2 प्रतिशत कम हुआ जो 40 प्रतिशत आर्थिक विकास के बावजूद आधार वर्ष (1990) से कम है। आधार वर्ष और 2008 के बीच ईयू–27[2] उत्सर्जन 13.2 प्रतिशत गिरा। ईयू–27 के लिए कोई सामूहिक क्योटो लक्ष्य नहीं है। ईयू में 2004 और 2007 में शामिल हुए बारह में से दस[3] के क्योटो प्रोटोकॉल के तहत अपनी अपनी वचनबद्धताएं हैं और उन्हें 2012 तक आधार वर्ष के मुकाबले उत्सर्जन 6 से 8 प्रतिशत घटाना है। क्योटो प्रोटोकॉल में साइप्रस और माल्टा के लिए उत्सर्जन लक्ष्य तय नहीं हैं।

[1] क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर के समय ईयू में जो पंद्रह देश शामिल थे उनके नाम हैं – ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लग्ज़मबर्ग, नीदरलैंड्स, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, ब्रिटेन।

[2] ईयू में इस समय 27 देश शामिल हैं।

[3] बल्गारिया, चेक गणराज्य, एस्तोनिया, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाक गणराज्य और स्लोवेनिया।

2020 के लिए तय किए गए महत्वाकांक्षी लक्ष्य

दिसम्बर, 2008 में यूरोपीय संघ ने इतिहास रचते हुए एक अभूतपूर्व जलवायु एवं ऊर्जा पैकेज अपनाया ताकि यूरोप को निम्नतम कार्बन अर्थ व्यवस्था में बदलकर ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इस पैकेज से अन्य देशों को भी स्वच्छ टैक्नोलॉजी उपलब्ध करायी जा सकेगी ताकि विकासशील देशों में भी उत्सर्जन में कटौती शुरू की जा सके।

इस पैकेज में 2020 के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 20 प्रतिशत कटौती करने का एकतरफा लेकिन कानूनी रूप से बाध्य लक्ष्य, नवीकरण योग्य ऊर्जा का हिस्सा 20 प्रतिशत तक ले जाना और ऊर्जा कुशलता में 20 प्रतिशत सुधार करना शामिल है। यह पैकेज 2009 के अंत में कोपनहेगन में होने वाले महत्वाकांक्षी जलवायु समझौते में अहम योगदान करेगा।

ईयू ने कोपनहेगन में 2012 के बाद की अवधि के लिए ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन 30 प्रतिशत तक कम करने की विश्व प्रतिबद्धता का पालन करने की पुष्टि की है, बशर्ते अन्य विकसित देश भी इतना ही लक्ष्य तय करें और आर्थिक रूप से उन्नत देश भी अपने दायित्वों को निभाएं।

ईयू–भारत सहयोग

ईयू–भारत साझेदारी में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन को संवाद और सहयोग का सामरिक क्षेत्र माना गया है और 2005 की ईयू–भारत संयुक्त कार्य योजना में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के मुद्दो पर सहयोग का आधार तय किया गया है।

ईयू का मकसद टिकाऊ विकास एवं गरीबी उन्मूलन की दिशा में भारत के प्रयासों को समर्थन देना और जलवायु परिवर्तन समेत विश्व पर्यावरण मुद्दों पर आपसी समझ विकसित करना है। ईयू ऊर्जा कुशलता, नवीकरण योग्य ऊर्जा, शोध एवं विकास, टैक्नोलॉजी हस्तांतरण और जल प्रबंधन के मार्केट आधारित उपकरण स्थापित करने में भी भारत के साथ सहयोग बढ़ा रही है। इन क्षेत्रों में सहयोग का आधार मार्सिले में सितम्बर 2008 में हुए भारत–ईयू शिखर सम्मेलन में पारित ऊर्जा, स्वच्छ विकास एवं जलवायु परिवर्तन पर कार्यक्रम को बनाया गया है।

ईयू भारत के साथ उसकी जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना की प्राथमिकताओं के बारे में सहयोग करने और अपने देशों को कम कार्बन उत्सर्जन वाली अर्थ व्यवस्थाओं में बदलने के लिए मजबूती से वचनबद्ध है।